

विविध बैंक प्रकरण संख्या 61/2020(GCMS : 2020/00146) ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लि.) रजि. ऑफिस 19ए धूलेश्वर गार्डन अजमेर रोड जयपुर-302001 तथा ऑफिस रविन्द्र पथ श्रीगंगानगर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी संजीव सेतिया पुत्र श्री प्रेमसागर सेतिया, निवासी 201 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर बनाम 1. सदालाल पुत्र बृजलाल 2. मोहित पुत्र सदालाल वीना देवी पत्नी देशराज निवासीगण वार्ड नं. 2, दुल्लापुरा केरी, चक 5 जी बड़ी, जिला श्रीगंगानगर



27.04.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री संजय भाटिया उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 13.08.2020 को प्रस्तुत किया था कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण सदालाल, मोहित एवं वीना देवी को ऋण सुविधा के रूप में 2.90/- लाख रुपये (अखरे रुपये दो लाख नब्बे हजार मात्र) का ऋण दिनांक 17.08.2018 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मोहित द्वारा अपनी सम्पत्ति आवासीय मकान पट्टा नं. 76, बुक नं. 297, ग्राम पंचायत दुलापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन है कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तों के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नहीं किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 10.06.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति(एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थीगण ऋणियों के नाम दिनांक 05.08.2019 को 3,13,533/- रुपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 23.08.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने के लिए जारी किया गया। उक्त धारा 13(2) के 60 दिवस नोटिस अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है तथा दो समाचार पत्रों में प्रकाशन

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

भी करवाया है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ऋणियों द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी लेखराम द्वारा सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय मकान पट्टा नं. 76, बुक नं. 297, ग्राम पंचायत दुलापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने, प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सदालाल, मोहित एवं वीना देवी को 2.90/- लाख रुपये (अखरे रुपये दो लाख नब्बे हजार मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 17.08.2018 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मोहित द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी सम्पत्ति आवासीय मकान पट्टा नं. 76, बुक नं. 297, ग्राम पंचायत दुलापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 10.06.2019 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.08.2019 को जारी कर पोस्ट ऑफिस के रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना अंकित किया है, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है तथा अप्रार्थी मोहिल को धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप प्राप्ति रसीद उपलब्ध है, जिस पर मोहित के स्वयं के हस्ताक्षर है तथा शेष अप्रार्थीगण सदालाल एवं वीना की प्राप्ति रसीद पत्रावली में उपलब्ध है जिन पर भी मोहित के हस्ताक्षर है परन्तु प्राप्ति रसीद पर कोई भी दिनांक एवं पोस्ट ऑफिस की मोहर अंकित नहीं है। इसके अतिरिक्त धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों दैनिक नव ज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 04.09.2019 को प्रकाशन करवाया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी मोहित की दृष्टि बंधक रखी गई सम्पत्ति आवासीय मकान पट्टा नं. 76, बुक नं. 297, ग्राम पंचायत दुलापुर केरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थीगण ऋणियों पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 23.08.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 23.08.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस अप्रार्थीगण सदालाल, मोहित एवं वीना देवी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना अंकित है परन्तु पोस्ट ऑफिस की रसीद पत्रावली में उपलब्ध नहीं है एवं अप्रार्थी मोहित को धारा 13(2) के नोटिस की प्राप्ति परिणामस्वरूप पोस्ट ऑफिस की प्राप्ति रसीद उपलब्ध है, जिस पर मोहित के स्वयं के हस्ताक्षर है तथा शेष की प्राप्ति रसीद पर भी मोहित के ही हस्ताक्षर है परन्तु प्राप्ति रसीद पर पोस्ट ऑफिस की मोहर एवं कोई दिनांक अंकित होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 04.09.2019 को करवाया है। वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम

2002 अन्तर्गत धारा 14 के अनुसार अप्रार्थीगण ऋणियों को धारा 13(2) का 60 दिवस का नोटिस जारी करने पर यदि अप्रार्थीगण ऋणियों पर नोटिस की तामील नहीं होती है और अप्रार्थीगण नोटिस की तामील से बचने का प्रयास करते हैं तो नोटिस की प्रति उनके निवास स्थान पर चस्पा कर दो समाचार पत्रों में धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन करवाना आवश्यक होता है परन्तु प्रार्थी बैंक ने धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 23.08.2019 को जारी कर पोस्ट ऑफिस की रजिस्टर्ड डाक से अप्रार्थीगण को भिजवाया है और अप्रार्थी मोहित के अलावा अन्य अप्रार्थीगण सदालाल एवं वीना देवी को रजिस्टर्ड नोटिस प्राप्त होने के परिणामस्वरूप स्वयं अप्रार्थीगण हस्ताक्षर की प्राप्ति रसीद प्रस्तुत नहीं की है और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत नियम 3(1) के परन्तुक के अनुसार अप्रार्थीगण के निवास स्थान पर नोटिस चस्पांदगी करने प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.08.2019 को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया है और 13(2) नोटिस भिजवाने के 12 दिन बाद ही समाचार पत्र दैनिक नवज्योति एवं इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 04.09.2019 को प्रकाशन करवाया है।

नोटिस तामील के सम्बन्ध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के नियम 3 निम्नानुसार अवलोकनीय है:

Demand Notice

(1) The service of demand notice as referred to in sub-section (2) of section 13 of the Ordinance shall be made by delivering or transmitting at the place where the borrower or his agent, empowered to accept the notice or documents on behalf of the borrower, actually and voluntarily resides or carries on business or personally works for gain, by registered post with acknowledgement due, addressed to the borrower or his agent empowered to accept the service or by

जिला बजिस्ट्रेट

सहायक

Speed Post or by courier or by any other means of transmission of documents like fax message or electronic mail service:

PROVIDED that where authorised officer has reason to believe that **the borrower or his agent is avoiding the service of the notice or that for any other reason, the service cannot be made as aforesaid, the service shall be effected by affixing a copy of the demand notice on the the outer door or some other conspicuous part of the house or building in which the borrower or his agent ordinarily resides or carries on business or personally works for gain and also by publishing the contents of the demand notice in two leading newspaper, one in vernacular language, having sufficient circulation in that locality.**

(2) Where the borrower is a body corporate the demand notice shall be served on the registered office or any of the branches of such body corporate as specified under sub rule(a)

(3) Any other notice in writing to be served on the borrower or his agent by authorised officer, shall be served in the same manner as provided in this rule.

(4) Where there are more than one borrower the demand notice shall be served on each borrower.

चूंकि प्रार्थीगण धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 23.08.2019 को जारी कर रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये हैं में प्रार्थी को 60 दिवस तक बकाया राशि जमा करवाने हेतु समय दिया गया था किन्तु उनके रजिस्टर्ड नोटिस की तामील की 60 दिवस तक प्रतीक्षा किये बिना एवं बंधक सम्पत्ति पर धारा 13(2) का नोटिस चस्प्रा किये बिना ही 12 दिवस के भीतर ही नोटिस पुनः जारी कर अखबारों में प्रकाशन करवा दिया, जो उक्त **THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002 के RULE 3 के तहत मान्य नहीं है।** इस प्रकार बैंक द्वारा ऋणी को तामील के सम्बन्ध में अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारो की अवहेलना की है। बैंक द्वारा विधिक प्रावधानों की अवहेलना कर नोटिस जारी करने से ऋणियों पर भी अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है। इसप्रकार ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की विधिवत् तामील होना नहीं माना जा सकता।

माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ ने 2012 Cr. I.R.(SC) 726 -

State of Bihar & Anr versus Arvind Kumar & Anr के पैरा-13 में भी निम्न प्रकार से निर्देश दिये है :

13. In Manish Goel Vs Rohini Goel, AIR 2010 SC 1099, this Court has held that generally, no Court has competence to issue a direction contrary to law nor the Court can direct an authority to act in contravention of the statutory provisions. The Courts are meant to enforce the rule of law and not to pass the orders or directions which are contrary to what has been injected by law. [see also : Vice Chancellor, University of Allahabad & Ors. Vs Dr. Anand Prakash Mishra & Ors., (1997) 10 SCC 264; and Karnataka State Road Transport Corporation Vs Ashrafulla Khan & Ors, AIR 2002 SC 629]

अतः उक्त विवेचन के आधार पर एवं कानूनी प्रावधानों की अवहेलना के कारण प्रार्थी एयू स्मॉल फाइनेन्स बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाण)

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
राजस्थान